बिहार में किसान आन्दोलन और कार्यरत संगठन : एक अवलोकन

ज्योति कुमारी*

कृषि प्रधान तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित भारतीय समाज का मुख्य तत्व यहाँ का किसान है। जो सदियों से भू–स्वामियों और सूदखोर साहूकारों के बहुआयामी शोषण का शिकार रहा है। संख्या में अधिक होने के बावजूद असंगठित तथा कमजोर होने के कारण यह कम संख्या वाले जमींदारों और साहूकारों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता रहा है। जमींदारों व साहूकारों को एक ओर तो अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन का समर्थन प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आन्दोलन के परिणामस्वरूप कांग्रेस जो भू–स्वामियों की समर्थक पार्टी थी, के डर से किसान जमींदारों से सीधी लड़ाई से बचना चाहते थें। कारण स्पष्ट था किसानों के बीच एकता का अभाव था, साथ ही उनका अपना कोई संगठन नहीं था।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बड़े पैमाने पर बंगाल से निलहे बागान मालिकों ने बिहार में आकर शरण ली और यहाँ के किसानों को अपने शोषण का शिकार बनाया। उनके खिलाफ किसानों ने सबसे पहले 1866–67 ई0 में मधुबनी के पंडौल नामक स्थान पर विद्रोह किया। 1883 ई0 में किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आन्दोलन किया। उनके उपरान्त तो उनके विद्रोहों का तांता लग गया। लेकिन ये सारे विद्रोह असंगठित थे। इसलिए तुरन्त ही इसे दबा दिया गया।[1]

लेकिन 1916–17 में चम्पारण में अंग्रेज नील कोठी वालों के खिलाफ किसानों का असंतोष पहली बार व्यापक और विस्फोटक बना। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चम्पारण में निलहों के खिलाफ सत्याग्रह किया गया और लम्बे समय से चले आ रहे तीन कठिया पद्धति का अन्त किया गया। यह चम्पारण सत्याग्रह किसान आन्दोलन और राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास में एक नींव स्तम्भ बन गया। कांग्रेस ने भी 1917 के बाद कृषकों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कृषक संघों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। नागरिक अवज्ञा आन्दोलन के बाद किसानों के स्वतंत्र संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई । किसान आन्दोलन के आगे बढे। उनकी यह भी मान्यता थी कि जब किसान अपने वर्ग की मांगों के साथ स्वराज्य के राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेंगे तभी यह संघर्ष सफल हो सकेगा। कांग्रेज, सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी कांग्रेस), कम्युनिस्ट पार्टी और जवाहरलाल नेहरू जैसे वामपंथी राष्ट्रवादियों ने देश में किसान–संगठनों की आवश्यकता पर जोर दिया।[2]

विश्वव्यापी आर्थिकसंकट ने कृषि अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त आघात किया। भारत केसभी हिस्सों में किसानों ने लगान बढ़ाने, कर्जदारों को गुलाम बनाने, जबरन जमीने छीनने की कार्रवाई के विरूद्ध आन्दोलन किये। कुर्क जमीनों की नीलामी का वहिष्कार करने और सूदखोर महाजनों के खिलाफ आपस में एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वतः स्फूर्त ढ़ंग से ग्राम समितियाँ बनाई। आर्थिक संकट से उत्पन्न तवाही ने भी बहुत हद तक किसानों को संगठित होने एवं अपनी रक्षा के लिए प्रेरितकिया जैसा रजनीपाम दत्त के शब्दों में कहा जा सकता है कि गॉवों, कस्बों में किसान संगठन बनने लगे तथा परस्पर मिलकर जिला एवं प्रान्तीय संगठनों का आविर्भाव हुआ।

इन संगठनों के अविर्भाव के साथ इन असंगठित विद्रोहों की तुलना में 20वीं सदी के बिहार में किसानों का संगठित आन्दोलन आरम्भ हुआ। एक तरफ, जहाँ 1917 के महात्मा गाँधी के चम्पारण के किसान सत्याग्रह ने साम्राज्यवाद विरोध के एक साथ कई सिद्धान्त स्थापित किये। एक यह राष्ट्रीय आन्दोलन मंच कांग्रेस का पहला किसान संघर्ष था। किसानों का यह सत्याग्रह किसी किसान संगठन के माध्यम से ना चलकर राष्ट्रीय आन्दोलन के मंच से चला।

इस तरह एक तरफ, गांधी ने 1917 में नीलहे साहबों के खिलाफ सत्याग्रह की शुरूआत की वहीं दरभंगा रियासत में 1920 में स्वामी विद्यानन्द के नेतृत्व में जमींदार–विरोधी व्यापक किसान आन्दोलन फूट पड़ा। राष्ट्रीय आन्दोलन के 1920 के दशक के उफान के दौर में किसानों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन जब किसानों का आन्दोलन जमींदारों से टकराने लगा तब कांग्रेस ने साफ तौर पर उनके नेतृत्व से इन्कार कर दिया। इस तरह कांग्रेस ने अपने जमींदार परस्त चेहरे को उजागर कर दिया, किसानों ने भी आन्दोलन की गॉधीवादी रणनीति का चौखट तोड़ दिया और 1921 ई0 में जब गाँधी ने किसानों से केवल कर न देने का आह्वान किया तो किसानों ने उसे लगानवंदी तक विस्तृत कर दिया। चम्पारण, पूर्णिया, फारविसगंज आदि इलाकों में किसानों ने पुलिस स्टेशन पर हमले किये, फसल लूट ली और अंग्रेजी सत्ता को सीधे चुनौती दी। एकाएक चौरा चौरी की धारणा की आड़ में गाँधी ने उस वक्त असहयोग आन्दोलन वापस लेने की घोषणा कर दी जब बिहार में कई ग्राम–रूट किसान नेता जेलों में बन्द थें। उन परिस्थितियों में राहुल सांकृत्यायन ने 1922 में 'प्रोविंशियल किसान सभा'[3] का गठन करके किसान आन्दोलन को नया वेग देने की कोशिश की, तो दूसरी ओर 1922–23 में मुंगेर में एक 'किसान सभा' की स्थापना शाह मुहम्मद जुबैर एवं श्री

***शोध छात्रा इतिहास विभाग, ल0ना0मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा**

कृष्ण सिंह के द्वारा की गयी। जिसके अध्यक्ष प्रमुख कांग्रेसी नेता शाह मुहम्मद जुबैर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, तथा सचिव नन्द किशोर सिंह और सुधेश्वरी चौधरी बने थें। इस तरह के कोशिश तो जरूर हुए, लेकिन 19225–28 के दौर में मधुबनी और गया के इलाकों में कुछेक जमींदार विरोधी आन्दोलन के बावजूद उस दिशा में कुछ खास सफलता हासिल नहीं हो सकी, राहुल सांकृत्यायन ने इसकी समीक्षा करते हुए लिखा 'किये गये प्रयास उपरिपक्व थें।'

बेगार (जबरदस्ती लिया गया काम), अवाव (गैर कानूनी वसूली), उपज लगान का नकद लगान में परिवर्त्तन, भावली दानाबंदी, निम्नजातियों के पट्टेदारों के सामाजिक सम्मान और वकाश्त जमीन के सवाल पर बिहार के किसान आन्दोलित थे और परिस्थितियॉ एक जुझारू किसान आन्दोलन के अनुकूल थी, इसी समय स्वामी सहजानन्द सरस्वती कांग्रेस के सम्पर्क में आये। वे असहयोग आन्दोलन में जेल यात्रा से लौटकर आने के बाद कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों से प्रभावित होकर 1924 में शाहाबाद के सिमरी ग्राम में चरखा और खादी का प्रचार शुरू किया। एक सन्यासी के बतौर भूमिहारों को ब्राहम्ण का दर्जा दिलवाने के संघर्ष से की गयी उनकी शुरूआत जल्दी ही एक नया आकार ग्रहण करने लगी। वे अपने भूमिहार, ब्राहम्ण महासभा के सहयोगियों के अनुरोध पर पटना जिले के बिहटा आये और वही 'श्री सीताराम आश्रम' की स्थापना की। यहीं स्वामी सहजानन्द का किसानों की दयनीय अवस्था का निकट से साक्षात्कार हुआ और उन्होंने आस–पास के किसानों के बीच घुम–घुम कर उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसी सिलसिले में उन्हें जमींदारों की जालिमाना हरकतों की कहानियों के साथ यह सुननेको मिला कि मसौढ़ी परगने के एक जमींदार ने किसानों की लड़लियों और गहने विकवा कर लगान वसूल किया था। सहजानन्द स्वामी पर इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई और 1927 के अंत तक वे इस क्षेत्र में किसान आन्दोलन संगठित करने लगे थें।[4] 4 मार्च 1928 को एक पैसा सदस्यता के आधार पर नियम कायदे के साथ बकायदा 'पश्चिमी पटना किसान सभा' का संगठन बनाया। घम–घूम कर किसान के हित में सहजानन्द व्याख्यान देने लगे। सामंतों और जमींदारों की मनोवृत्ति को भीतर से देखकर स्वामी सहजानन्द की आँखें खुलने लगी। सदियों की सत्यानाशी भावली, मनमानी दानावंदी, कईनकदी, सैकड़ों गैर कानूनी अत्याचार, नजर तहरीर, बैठ बेगारी, दण्ड–जुर्माना, जमींदारों द्वारा जमीन से बेदखली आदि मनमानी लूट ने किसानों की कमर तोड़ डाली थी। उन विवशताओं के चलते किसानों को विविध अमानुषिक अत्याचार तक सहना पड़ता था।[5]

स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा पटना क्षेत्र के किसानों को राहत के लिए किये गये संघर्षों ने राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्य नेताओं का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया। यही कारण था कि 'बिहार काश्तकारी कानून' में किसान के हित

के खिलाफ संशोधन लाने की बात जब बिहार सरकार कर रही थी तब राम दयालू सिंह, श्री कृष्ण सिंह, यमुना कार्यी आदि नेताओं ने स्वामी सहजानन्द को प्रान्तीय स्तर पर 'किसान सभा' संगठित करने के लिए तैयार किया। 5 नवम्बर 1929 में सोनपुर मेले में प्रथम बिहार प्रान्तीय किसान सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में 'बिहार प्रान्तीय किसान सभा' की बजाप्ता सीापना की गयी।[6]

मेले में किसान सभा के उद्धेश्यों एवं कार्यक्रमों पर स्वामी सहजानन्द की अध्यक्षता में भाषण हुआ। किसान सभा के सभापति स्वामी सहजानन्द हुए। श्री कृष्ण सिंह को जेनरल सेक्रेटरी, यमुना कार्यी, गुरू सहाय लाल, कैलाश बिहारी लाल को डिविजनल सेक्रेटरी चुना गया।[7] इसके सदस्यों में बिहार के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का नाम दिया गया। एवं उनसे स्वीकृति ली गयी। ब्रजकिशोर प्रसाद के अतिहरक्त सबने स्वीकृति दी।[8] कुछ लोगों को बाद में शामिल किया गया।

1929 ई0 में बिहार प्रदेश किसान सभाा का गठन होते ही महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि सरकार ने पट्टेदारी कानून में संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लिया, किसानों ने इसे एक महत्वपूर्ण जीत समझा और उनका मनोवल अपनी बुलन्दी पर पहॅूच गया। सम्मेलन में फसल लगान की दानाबंदी प्रणाली के खिलाम प्रस्तावों को भी बहस के लिए पेश किया गया।

किसान सभा के अनगिनत स्थानीय नेताओं में यमुना कार्यी, यदुनन्दन शर्मा, कर्यानन्द शर्मा, शीलभद्र भाषी शामिल थे। आने वाले दिनों में नागार्जुन जैसे बुद्धिजीवी और जय प्रकाश नारायण, रामवृक्ष वेनीपुरी, गंगाशरण सिंह, अवधेश्वर प्रसाद सिंह और रामनन्दन मिश्र जैसे सोशलिस्ट नेता भी शामिल हुए। सहजानन्द सरस्वती के साथ जुड़कर राहुल सांकृत्यायन ने भी कई किसान आन्दोलनों का नेतृत्व किया।

'बिहार प्रान्तीय किसान सभा' के संगठनाकर्ताओं का प्रारम्भिक उद्धेश्य किसान आन्दोलन को इस रूप में संचालित करना था जिससे जमींदार और काश्तकार में संघर्ष नहीं बढ़े तथा कांग्रेस को लेजिस्लेटिव कॉसिल का चुनाव जीतने में मदद मिले। स्वतंत्र स्वामी सहजानन्द भी जिस समय विहटा के आस–पास किसानों के बीच घूम रहे थें उसी सतय तक वह पक्के कॉग्रेसी थे। अब तक वह जमींदारों और किसानों के परस्पर विरोधील अधिकारों और हितों के सामंजस्य में विश्वास रखते थे। इस प्रकार मूलतः इसका उद्धेश्य सुधारवादी था, जुझारू रूप इसके बाद उभरा था।[9]

15 दिसम्बर, 1929 को प्रान्तीय किसान कॉसिंल ने किसान सभा का संविधाण स्वीकृत किया। संविधान के अनुसार सभा का उद्धेश्य किसानों की खामियों और शिकायतों को संगठित बल पर अहिंसात्मक तरीके से दूर करना था।

जनवरी 1930 में किसान सभा की एक विशेष बैठक में इस संशोधन का विरोध किया गया और स्वराज्य पार्टी ने भी कॉसिल में इसी आधार पर उक्त संशोधन विरोध किया। अन्ततः सरकार ने इस प्रबल विरोध की संभावना को देखते हुए यह बिल वापस ले लिया।[10]

इस प्रकार बिहार प्रान्तीय किसान सभा की प्रारम्भ में ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सभा की स्थापना का तत्कालीन उद्धेश्य पूरा हुआ।

1930–31 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने के कारण स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने किसार सभा की पृथक गतिविधि स्थगित कर दी थी और अब किसानों का असंतोष भी व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन का अंग बन गया था।[11] यद्यपि सारा राष्ट्र 1930 के प्रारम्भ से सविनय अवज्ञा आन्दोलन के उताल तरंगों में शरीक हो गया था। बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसान भी जोश–खरोश के साथ उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे और नव निर्मित किसान आन्दोलन के नेता भी राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करना चाहते हैं। अतः उन्होंने किसान सभा को बजाप्ता गतिविधियों को स्थगित कर दिया था तथापित विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से उत्पन्न स्थिति से ऑखें नहीं मूदी जा सकती थी।

अतः 1930–1934 के राष्ट्रीय आन्दोलन के दौर में भी कांग्रेस और किसान सभा के नेताओं को किसानों की समस्याओं को लेकर कई प्रकार के कदम उठाने पड़े।[12]

इस तरह बिहार में ताकलवर किसान आन्दोलन का जन्म आधारभूत तौर पर कठोर खेतिहर प्रथा के दवाव के प्रतिक्रिया में था जिसे बुलन्दगी आर्थिक मंदी के दुस्परिणामों से मिला। इन दवावों प्रतिउत्तर ने, अलवेला नेतृत्व और राजनीतिक उभार के प्रभाव में, संगठित रूप, बिहार प्रान्तीय किसान सभा के रूप में लिया।

मार्च 1933 के बाद में एक वर्ष में किसान सभा बिहार में एक शक्तिशाली संगठन के रूप में संगठित हो गयी। अब यह यूनाइटेड पार्टी की विरोधी संस्था ही नहीं रह गयी बल्कि यह किसानों की माँगों को लेकर आगे बढ़ती हुई उनके हितों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यहाँ तक कि मुंगेर की एक सभा में यह निर्णय लिया गया कि किसान आधे से अधिक लगान नहीं देंगे।[13] कांग्रेस द्वारा किसानों को गाँधीवादी सीमा में रखने के प्रयास के कारण स्वामी सहजानन्द विफर उठे थे। सही मायने में किसान सभा का नेतृत्व गाँधीवादी राष्ट्रीयता की उपज था। लेकिन विकसित होते हुए जब यह गाँधीवादी विचार धारा और तरीका को पर्याप्त समझने से राजनीतिक और आर्थिक उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु निराश हो गया तब नेतृत्व वामपंथी की ओर मुड़ा और इस तरह वर्ग आधारित किसान आन्दोलन की पैदाइश हुई।[14]

इस तरह शुरू में तो सहजानन्दन सरस्वती महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व एवं उनके कार्यक्रमों से अविभूत हुए लेकिन धीरे–धीरे गाँधीवादी कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन के प्रति उनमें उदासीनता का भाव पैदा होने लगा। उन्होंने महशुस किया कि कांग्रेस के उपर पूँजीवादी बुर्जुआ नेतृत्व हावी है। उससे किसानों एवं मजदूरों के हित साधन की कामना नहीं की जा सकती थी। अस्तु, कांग्रेस में रहकर ही उन्होंने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसी उद्धेश्य से 1933 ई0 मुं उन्होंने 'बिहार किसान सभा' का गठन किया।[15] 18 जून, 1933 ई0 को प्रान्तीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति ने किसानों की दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया। स्वामी सहजानन्द सरस्वती, यमुना कार्यी, यदुनन्दन शर्मा और डॉ0 युगल किशोर सिंह इसके सदस्य थे। इस समिति ने रिपोर्ट प्रकाशित किया।

इस सम्मेलन के प्रस्तावों के तहत् विभिन्न जिलों में बिहार प्रदेश किसान सभा की सैकड़ों सभाएँ आयोजित की गयी।

1934 ई0 में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा कॉग्रेस के अन्दर 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' का गठन किया गया। 1933–1935 तक पुरे बिहार में लगभग 500 किसान यूनिटे गठित की गई। स्वामी सहजानन्दन ने इसी समय पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57, शाहाबाद में 39, भागलपुर में 22, दरभंगा में 38, सारण में 19, पूर्णिया में 13, किसान सभाओं को सम्बोधित किया। आन्दोलन के चरण काल तक लगभग 5000 स्थानीय किसान सभाएँ और पटना में 1,00,000 से उपर की किसान रैली आयोजित हुई। उन समाओं में ''कैसे लोग मालगुजारी, लटठमहारी, जिन्दाबाद'' के नारे पर किसान जादू के जोर से खिंचे चले आते थें। 1935 में किसान सभा के सदस्य संख्या अनुमानतः 80,000 थी जो 1938 में 2,50,000 तक पहूँच गई। इस तरह किसान सभा आन्दोलन का स्थानीय नेतृत्व 1935 में बहुत ही प्रभावी था और आन्दोलन प्रगति कर रहा था। इन लोगों में स्वामी सहजानन्द, यदुनन्दन शर्मा, गंगाशरण सिंह, तथा कुछ अन्य किसान नेता जगह–जगह सभाएँ करते और आन्दोलन को जोरदार बनाते फिरते दिखे।

इन्ही दिनों बिहार किसान संगठन की देखा देखी में अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रान्त में किसान संघ की स्थापना हुई। इसके कार्यक्रम में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन की मांग की। इसी वर्ष प्रो0 एन0जी0 रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सब प्रान्तीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की तैयारी के लिए और उनका आगे का कार्यक्रम बनाने के लिए मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया। इस प्रक्रिया के तहत 1936

में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना जिसे 'अखिल भारतीय किसान सभा' नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनउ में ठीक उसी समय हुआ, जब वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था। इस अधिवेशन में 1 सितम्बर, 1936 को 'किसान दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया। किसान सभा पर प्रोफेसर रंगा के अतिरिक्त वामपंथी कांग्रसियों, कम्युनिष्टों एवं स्वामील सहजानन्द सरस्वती जैसे प्रगतिशील किसान नेताओं क काफी प्रभाव था। इन दिनों बढ़ते हुए किसान आन्दोलनों एवं किसान सभा की तेजी से बढ़ती हुई सदस्यता तथा प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने इस दौरान किसानों को राहत देने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाये।[16]

इस तरह 1936 में 'अखिल भारतीय किसान सभा' का जन्म हुआ और बिहार प्रदेश किसान सभा इसकी सबसे बड़ी प्रान्तीय इकाई बन गई। इसके निर्माण में मुख्य भूमिका कॉग्रेस–सोशलिष्टों की थी। लखनउ में सम्पन्न इसकी पहली बैठक में स्वामी सहजानन्दन को इसका अध्यक्ष चुना गया। लेकिन स्वामी सहजानन्द के मन में उसके निर्माण के बारे में अनेक तरह की शंकाएँ थीं। वे महसूस कर रहे थें कि विकसित प्रान्तीय इकाईयों के अभाव में राष्ट्ररीय संगठन कोई कारकर भूमिका नहीं अदा कर सकता। गांधी व कांग्रेस से पूरी तरह मोहभंग के बादवे सुभाषचन्द्र बोस का समर्थन किया।[17]

इस बीच मध्य बिहार में कर्मानन्द शर्मा के नेतृत्व में बड़हिया में वकाश्त आन्दोलन शुरू हुआ। कर्मानन्द ने साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण कर भारत में पहली बार किसान आन्दोलन को साम्यवादी ढ़ंग से चलाया। 1939 ई0 के अन्त में प्रान्तीय सरकार के त्याग पत्र एवं खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि के पश्चात् आन्दोलन गति मन्द होने लगी। यदुनन्दन शर्मा ने गया जिला के रेउड़ा में रामनन्दन मिश्र ने दरभंगा जिला में, राहुल सांकृत्यायन ने छपरा में तथा यमुना कार्यी ने सारण में इसी तरह के आन्दोलन संचालित किये। द्वितीय विश्वयुद्ध तक जाते–जाते स्वंय स्वामी सहजानन्द सरस्वती मार्क्सवादी विचार धारा की आकृज होने लगे और वर्ग संघर्ष के आधार पर उन्होंने किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके कारण जय प्रकाश नारायण ने 'रेड किसान सभा' का गठन कर लिया।[18] जय प्रकाश नारायण 1942 के आन्दोलन के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे। उनके नेतृत्व में किसानों ने 1942 ई0 के भारत छोड़ो आन्दोलन को यादगार आन्दोलन के रूप में परिवर्त्तित कर दिया और भारत की आजादी को काफी करीब जा दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को अब एहसास हो गया कि भारत के गॉव–गॉव में जन आन्दोलन फेल चुका था और उसे कुचलना उनके बस की बात नहीं थी।[19]

इस प्रकार बिहार के किसान संगठनों ने न केवल किसानों की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया बल्कि भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन को भी गति प्रदान की।

सन्दर्भ

1. प्रमोदानन्द दास एवं कुमार अमरेन्द्र, बिहारः इतिहास एवं संस्कृति, पटना, 2008, पृ0 233
2. ए0आर0 देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, नई दिल्ली, 1985, पृ0 153
3. कुमार परवेज, 'किसान सभा आन्दोलन और स्वामी सहजानन्द सरस्वती की वैचारिकता',, अभिनव कदम, वर्ष–16, अंक 26, दिसम्बर 2011–मई 2012, कृ0–304
4. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पटना, 1952, पृ0–136
5. त्रिवेणी शर्मा सुधाकर, युग पुरूष स्वामी सहजानन्द सरस्वती की जीवन झॉकी, स्वामी सहजानन्द सरस्वती स्मृति ग्रन्थ, प्रथम भाग, पृ0 04
6. सोनपुर मेला किसान मीटिंग, गवर्नमेन्ट ऑफ बिहार और उड़ीसा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट (स्पेशल सेक्सन) फाइल नं0 281/1929 और स्वामी सहजानन्द सरस्वती, पूर्वोक्त, पृ0 334–349
7. के0के0दत्त, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, पटना 1957 खण्ड 2, पृ0 235
8. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, किसार सभा के संस्मरण, बिहटा, पटना 1946,पृ02
9. विजय किशोर, पूण्य संस्करण, 12 हूँकार, 16 जून, 1982
10. स्वामी सहजानन्द सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पूर्वोद्धत, पृ0 345
11. राकेश गुप्ता, बिहार पीजेन्टरी एण्ड किसान सभा, दिल्ली, 1982 पृ0 91–92
12. के0के0 दत्त, पूर्वोद्धत, पृ0 210
13. बिहार सरकार, पाक्षिक रिर्पोट, मार्च, 1933, द्वितीय पखवारा।
14. वाल्टर हाउजन, पूर्वोद्धत, पृ0 76
15. द सर्चलाइट, 12 मई 1933
16. प्रमोदानन्द दास एवं कुमार अमरेन्द्र, पूर्वोद्धत,पृ0 234
17. पी0एल0गौतम, आधुनिक भारत (1757–1964), जयपुर, 1998, पृ0 661
18. कुमार परवेज, पूर्वोद्धत, पृ0 308
19. प्रमोदानन्द दास एवं कुमार अमरेन्द्र, पूर्वोद्धत, पृ0 235